



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1664]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 13, 2017/ज्येष्ठ 23, 1939

No. 1664]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13, 2017/JYAISTHA 23, 1939

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2017

**का.आ. 1877(अ).—** सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, भारत सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्रालय का उर्वरक विभाग (जिसे इसके पश्चात् इसे विभाग कहा गया है) विनिर्दिष्ट फास्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों, यूरिया तथा शहरी कम्पोस्ट के लिए केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमों के रूप में उर्वरक सहायकी स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) देश भर में अलग-अलग स्कीमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत विभिन्न उर्वरक विनिर्माताओं और आयातकर्ताओं द्वारा उनके खुदरा विक्रेताओं और वितरकों के माध्यम से किसानों (जिसे इसमें इसके पश्चात् हिताधिकारी कहा गया है) को सहायता प्राप्त कीमतों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभ कहा गया है) बिक्री के लिए नीचे उल्लिखित उर्वरक सहायता प्राप्त स्कीमों का देश की खाद्य सुरक्षा के हित में प्रशासन कर रहा है:

- i. यूरिया के आयात हेतु संदाय के लिए यूरिया सहायकी मुख्य शीर्ष 2852
- ii. यूरिया मालभाड़ा सहायकी हेतु संदाय के लिए यूरिया सहायकी मुख्य शीर्ष 2852
- iii. स्वदेशी यूरिया के लिए संदाय हेतु यूरिया सहायकी मुख्य शीर्ष 2852
- iv. शहरी कम्पोस्ट के लिए संदाय हेतु पोषक-तत्व आधारित सहायकी नीति मुख्य शीर्ष 2401
- v. आयातित पीएण्डके उर्वरकों के लिए संदाय हेतु पोषक-तत्व आधारित सहायकी नीति मुख्य शीर्ष 2401
- vi. स्वदेशी पीएण्डके उर्वरकों के लिए संदाय हेतु पोषक-तत्व आधारित सहायकी नीति मुख्य शीर्ष 2401

और जबकि इन स्कीमों के अधीन सहायकी में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित है:

अतः अब केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) स्कीमों के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार नंबर रखने का अथवा आधार प्रमाणीकरण कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(2) स्कीमों के अधीन लाभ लेने/प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, जिसके पास आधार नम्बर नहीं है अथवा जिसने अभी आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उससे 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार के लिए पात्र हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, वह मंत्रालय जो व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है उससे अपने कार्यान्वयन अभिकारणों और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से आधार के लिए अभी तक नामांकन न करने वाले हिताधिकारियों हेतु आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और संबंधित ब्लॉक अथवा तालुका और तहसील में आधार नामांकन केन्द्र नहीं होने की स्थिति में मंत्रालय के लिए अपने कार्यान्वयन अभिकारणों और अपने फ़िल्ड कार्यालयों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से अथवा मंत्रालय को स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर अब सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है:

परन्तु स्कीम के अधीन व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने तक स्कीम के अधीन निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए लाभ दिया जाएगा, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी/उसका आधार नामांकन आईडी पर्ची या

(ii) आधार नामांकन के लिए उसके अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) (i) किसान क्रेडिट कार्ड; अथवा (ii) मतदाता पहचान पत्र अथवा (iii) मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक तथा बाधरहित लाभ प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकारणों तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:—

(क) स्कीमों के अधीन हिताधिकारियों को आधार की अपेक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए उसमें व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यक्तिगत सूचनाएं दी जाएगी और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वयं को 30 जून, 2017 तक स्वयं को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जाए, यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (केन्द्रों की सूची [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची) उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) यदि, हिताधिकारी ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील जैसे निकटतम स्थान पर नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण आधार हेतु नामांकन करने में असमर्थ हैं तो मंत्रालय को अपने कार्यान्वयन अभिकारणों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, अब सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है तथा मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों अथवा कार्यान्वयन अभिकारण अथवा कार्यान्वयन अभिकारणों के खुदरा विक्रेता अथवा वितरकों के साथ इस प्रयोजन के लिए दी गई वेब पोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अपने नाम, पता, मोबाइल नं. तथा अन्य विवरण देकर आधार नामांकन हेतु अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत करने का अनुरोध हिताधिकारियों से किया जाए।

3. यह अधिसूचना प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) महत्वकांक्षी जिलों तथा अन्य जिलों, जब कभी उन्हें असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के अंतर्गत लाया जाता है, में राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. डी(एफए)/डीबीटी/2016(पीटी.आई)]

धर्मपाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CHEMICAL AND FERTILIZERS****(Department of Fertilizers)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th May, 2017

**S.O. 1877(E).**—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, Department of Fertilizers (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Chemical and Fertilizers in the Government of India is administering below mentioned Fertilizer Subsidy Schemes (hereinafter referred to as the Schemes) as Central Sector Schemes for Specific Phosphatic and Potassic Fertilizers, Urea and City Compost through different fertilizer manufacturers and importers (hereinafter referred to as the Implementing Agencies) registered under the respective Schemes across the country for sale of different fertilizers at subsidized prices (hereinafter referred to as the benefit) to the farmers (hereinafter referred to as the beneficiaries) through their retailers and distributors in the interest of country's food security:.

- i. Urea subsidy MH 2852 payment for Import of Urea;
- ii. Urea subsidy MH 2852 payment for Urea freight subsidy;
- iii. Urea subsidy MH 2852 payment for Indigenous Urea;
- iv. Nutrient based subsidy policy MH 2401 payment for City Compost;
- v. Nutrient based subsidy policy MH 2401 payment for imported P and K fertilizers;
- vi. Nutrient based subsidy policy MH 2401 payment for indigenous P and K fertilizers;

And whereas, the subsidy under the Schemes involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Schemes is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing/receiving benefits under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 30<sup>th</sup> June, 2017 provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies and their field offices, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies and their field offices is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming UIDAI Registrar :

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:—

- (a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of her or his request made for Aadhaar Enrolment.
- (b) (i) Kisan Credit Card; or (ii) Voter Identity Card; or (iii) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Schemes, the Ministry through its Implementing Agencies and their field offices shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30<sup>th</sup> June 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries the Schemes are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies and their field offices is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Ministry or the Implementing Agency or Retailers or Distributors of Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in the Direct Benefit Transfer (DBT) Pilot Districts and other districts as and when they are brought under DBT in all the States except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No. D(FA)/DBT/2016 (Pt.I)]

DHARAM PAL, Jt. Secy.